PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 035
दि. 04.06.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तीन साल के इंतजार के बाद डीके शिवकुमार के हाथों में कर्नाटक की कमान, भव्य शपथ ग्रहण के साथ शुरु हुआ सत्ता का नया अध्याय

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में पिछले तीन वर्षों से चल रहा नेतृत्व परिवर्तन का लंबा अध्याय आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संगठन के कुशल रणनीतिकार और राज्य की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कर्नाटक की सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। राजधानी बेंगलुरु में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेतृत्व की एकजुटता, शक्ति प्रदर्शन और आगामी राजनीतिक दिशा की स्पष्ट झलक देखने को मिली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता जी. परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि 13 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। कर्नाटक की राजनीति में यह केवल सत्ता परिवर्तन भर नहीं माना जा रहा, बल्कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रहे नेतृत्व संतुलन के प्रयासों का परिणाम भी माना जा रहा है। डीके शिवकुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जाते रहे हैं। संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति तैयार करने और कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर व्यापक सहमति रही है। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने को कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी राजनीतिक यात्रा की स्वाभाविक परिणति के रूप में देख रहे हैं।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले डीके शिवकुमार ने जिस तरह अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत यात्रा को सम्मान दिया, उसने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक रंग भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले वह सीधे अपनी मां गौरम्मा के आवास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण से पहले मां के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने की तस्वीरें पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गईं। इसके बाद वे लोक भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं, संत समाज और हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लोक भवन परिसर में पहुंचते ही शिवकुमार ने सबसे पहले वहां उपस्थित संतों और धर्मगुरुओं का अभिवादन किया। संत समाज ने उन्हें पारंपरिक पटका पहनाकर सम्मानित किया और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। यह दृश्य

कांग्रेस के भीतर एकता और सामंजस्य का प्रतीक माना गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया।

शपथ ग्रहण समारोह का सबसे चर्चित दृश्य तब देखने को मिला जब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे। उनके हाथ में लाल रंग की संविधान की प्रति थी। संविधान की प्रति को हाथ में लेकर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीकात्मक संदेश था। जैसे ही उन्होंने शपथ पूरी की, समारोह स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शपथ के बाद उन्होंने मंच से जनता का अभिवादन करते हुए सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री के बाद जी. परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता के रूप में उनकी नियुक्ति को सामाजिक संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से पार्टी संगठन और सरकार में सक्रिय भूमिका निभाने वाले परमेश्वर को राज्य की सत्ता संरचना में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह सामाजिक समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहती है।

इसके बाद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने एक-एक कर पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं और नए चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिला। के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायर गौड़ा, प्रियांक खरगे, यू.टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, बैरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। सबसे अधिक चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया के मंत्री बनने को लेकर रही। उनकी नियुक्ति को कांग्रेस के भीतर नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। नए मंत्रिमंडल की संरचना पर नजर डालें तो कांग्रेस ने क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सरकार के भीतर सभी प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि आने वाले वर्षों में राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखा जा सके। यही कारण है कि मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों को भी अवसर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह अपनी भव्यता और व्यापक व्यवस्थाओं के कारण भी चर्चा में रहा। लोक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यभर से आए हजारों समर्थकों और विशेष आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री शिवकुमार के परिवार के सदस्य भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। उनकी मां गौरम्मा, पत्नी उषा और बच्चों की उपस्थिति ने समारोह को पारिवारिक और भावनात्मक स्वरूप भी प्रदान किया।

समारोह में राजनीतिक नेताओं के अलावा धार्मिक गुरु, उद्योगपति, फिल्म जगत की हस्तियां और खेल जगत से जुड़े अनेक प्रमुख व्यक्तित्व भी मौजूद रहे। चालीस से अधिक धर्मगुरुओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया। कन्नड़ फिल्म उद्योग से अभिनेता रविचंद्रन, किच्चा सुदीप, अभिनेत्री जयमाला और रम्या जैसे कलाकार उपस्थित रहे। खेल जगत से पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी समारोह का हिस्सा बनीं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि शिवकुमार का राजनीतिक प्रभाव केवल पार्टी और सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों तक फैला हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में एक और विशेष बात देखने को मिली। परंपरा के अनुसार ऐसे आयोजन आमतौर पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम पूर्व दिशा की ओर मुख करके संपन्न कराया गया। बताया गया कि यह निर्णय आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सलाहकारों की सलाह के आधार पर लिया गया था। इस निर्णय ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पूरे कार्यक्रम में सांस्कृतिक तथा पारंपरिक तत्वों की उपस्थिति को रेखांकित किया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिहाज से भी यह समारोह बेहद व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया था। लोक भवन परिसर स्थित 'ग्लास हाउस' को विशेष रूप से सजाया गया था। लगभग 3,500 अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। धर्मगुरुओं के लिए अलग से विशेष स्थान निर्धारित किया गया था। कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि को सभी तक पहुंचाने के लिए छह बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थीं। इसके अलावा 2,000 से अधिक वीआईपी पास जारी किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे ताकि समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। राजनीतिक दृष्टि से डीके शिवकुमार के सामने अब कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र की समस्याएं और कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वादों को पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही उन्हें पार्टी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि शिवकुमार का प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता राज्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कर्नाटक की राजनीति में यह शपथ ग्रहण केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सत्ता के नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के लिए यह अवसर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को जमीन पर उतारने का है, जबकि डीके शिवकुमार के लिए यह वर्षों के राजनीतिक संघर्ष और संगठनात्मक मेहनत का परिणाम है।

सोशल मीडिया आंदोलन से राजनीतिक मंच तक: कॉकरोच जनता पार्टी ने बढ़ाए कदम, तीन प्रवक्ताओं की घोषणा से तेज हुई चर्चा

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक विरोध अभियान अब संगठित राजनीतिक स्वरूप लेने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नाम से चर्चित समूह ने पहली बार औपचारिक रूप से अपने प्रवक्ताओं की घोषणा कर राजनीतिक गतिविधियों के संकेत दिए हैं। संगठन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच 'कॉकरोच इज बैक' के माध्यम से तीन प्रमुख चेहरों को प्रवक्ता नियुक्त करने की जानकारी साझा की है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सोशल मीडिया जगत में नई बहस शुरू हो गई है कि क्या यह अभियान आने वाले समय में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के रूप में उभरने की तैयारी कर रहा है। सीजेपी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार खोजी पत्रकार सौरव दास को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। उनके साथ राजनीतिक शोधकर्ता, लेखिका और फिल्म निर्माता विजेता दहिया तथा आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र एवं वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी मैकिंजी से जुड़े रहे आशुतोष रांका को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देना और युवाओं को केंद्र में रखकर संवाद की नई संस्कृति विकसित करना है। प्रवक्ताओं की

घोषणा के साथ ही संगठन ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहने के बजाय अपने विचारों और मुद्दों को संगठित तरीके से जनता तक पहुंचाना चाहता है। सीजेपी का दावा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है तथा पारंपरिक राजनीतिक दल इन विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में नई पीढ़ी के नेतृत्व को सामने लाकर एक वैकल्पिक राजनीतिक संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य प्रवक्ता बनाए गए सौरव दास को कानूनी, न्यायिक और सामाजिक विषयों पर खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। संगठन का दावा है कि वर्ष 2025 में नई दिल्ली के इंडिया गेट क्षेत्र में आयोजित प्रदूषण विरोधी आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता और सार्वजनिक बहसों में उनकी भागीदारी को देखते हुए उन्हें संगठन का प्रमुख चेहरा बनाया गया है। माना जा रहा है कि मीडिया और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिल सकता है। दूसरी प्रवक्ता विजेता दहिया का परिचय भी बहुआयामी है। वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर शोध आधारित सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रिय उपस्थिति रही है और उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय सिनेमा में लेखन और निर्देशन से जुड़े उनके कार्यों ने भी उन्हें पहचान दिलाई है। संगठन का मानना है कि शोध, संस्कृति और सामाजिक विमर्श के क्षेत्र में उनका अनुभव पार्टी की विचारधारा को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने में सहायक होगा। तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका तकनीकी और वैश्विक प्रबंधन पृष्ठभूमि से आते हैं। आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परामर्श कंपनी मैकिंजी में कार्य किया। पिछले वर्ष भारत लौटने के बाद वे पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और युवाओं से जुड़े विभिन्न अभियानों में सक्रिय रहे हैं। संगठन को उम्मीद है कि उनका वैश्विक अनुभव और नीति संबंधी समझ पार्टी के विचारों को व्यावहारिक स्वरूप देने में उपयोगी सिद्ध होगी। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा केवल उसके नाम के कारण ही नहीं, बल्कि उसके जन्म की पृष्ठभूमि के कारण भी हो रही है। दरअसल यह अभियान उस समय चर्चा में आया था जब बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चल रही बहस के दौरान एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में युवाओं ने विरोध दर्ज कराया और उसी क्रम में 'कॉकरोच जनता पार्टी' नामक अभियान की शुरुआत हुई। देखते ही देखते यह नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हजारों युवाओं ने इसे प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपनाया। इस अभियान के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के निवासी बताए जाते हैं। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा से जुड़े मुद्दों और युवाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिले दो स्थायी जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्तियों पर लगाई मुहर

नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। कॉलेजियम के इस निर्णय को न्यायपालिका में स्थिरता, दक्षता और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार 2 जून 2026 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपेंद्र सिंह नलवा को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। दोनों न्यायाधीश फिलहाल अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब उन्हें स्थायी रूप से उच्च न्यायालय की पीठ में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्ति मिलना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह उस न्यायालय की संस्थागत मजबूती का भी संकेत होता है। स्थायी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण की गति तेज होने की उम्मीद रहती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट देश के सबसे महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है, जहां पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े लाखों मामलों की सुनवाई होती है।

कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत दोनों नामों को न्यायिक क्षेत्र में अनुभवी और सक्षम माना जाता है। न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपेंद्र सिंह नलवा ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई की है। उनके कार्य निष्पादन, निर्णयों की गुणवत्ता, न्यायिक व्यवहार और प्रशासनिक क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद ही कॉलेजियम ने उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थायीकरण की प्रक्रिया संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत संचालित होती है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि नियुक्ति की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यक्षमता, ईमानदारी, न्यायिक दृष्टिकोण और समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजता है। किसी अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया भी काफी विस्तृत और पारदर्शी मानी जाती है। इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश के कार्य निष्पादन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण आंकड़े और रिपोर्ट कॉलेजियम को उपलब्ध करानी होती हैं। इनमें न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, निर्णयों की गुणवत्ता, लंबित मामलों का अनुपात, न्यायिक अनुशासन और समग्र कार्यशैली से संबंधित जानकारी शामिल होती है। इन सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करने के बाद ही कॉलेजियम अंतिम निर्णय तक पहुंचता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या होना न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। देश के अधिकांश उच्च न्यायालय लंबे समय से न्यायाधीशों के रिक्त पदों और बढ़ते लंबित मामलों की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऐसे में समय-समय पर होने वाली नियुक्तियां न्यायिक तंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं और न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का महत्व इस दृष्टि से भी विशेष है कि यह दो राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय है। कृषि, उद्योग, भूमि विवाद, प्रशासनिक मामलों, सेवा संबंधी विवादों और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े हजारों मामले यहां प्रतिवर्ष दाखिल होते हैं। इसलिए न्यायालय में अनुभवी और स्थायी न्यायाधीशों की उपलब्धता न्यायिक कार्यों की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। कॉलेजियम की इस सिफारिश के बाद नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने पर दोनों न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति अधिसूचित की जाएगी।

अल नीनो का बढ़ता खतरा: सूखे की आशंका ने बढ़ाई चिंता, केंद्र ने राज्यों को तुरंत तैयारी के निर्देश दिए

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन और लगातार बदलते मौसमीय पैटर्न के बीच दुनिया एक बार फिर संभावित मौसमीय संकट की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों के लिए आने वाले तीन महीने चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा जारी ताजा चेतावनी ने इस आशंका को और गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने संकेत दिया है कि प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ रहा समुद्री तापमान अल नीनो की स्थिति को जन्म दे सकता है, जिसके कारण जून से अगस्त के बीच दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, भीषण गर्मी और मौसम संबंधी असामान्य घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। भारत भी इस संभावित प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा, जिसके चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने और तत्काल कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना लगभग 80 प्रतिशत आंकी गई है। एजेंसी का अनुमान है कि वर्ष के अंतिम महीनों तक यह प्रभाव और मजबूत हो सकता है तथा नवंबर तक इसके बने रहने की संभावना 90 प्रतिशत से भी अधिक है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति विकसित होती है तो इसका असर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम चक्र पर दिखाई देगा। भारत के लिए यह चेतावनी इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की कृषि व्यवस्था, जल संसाधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। देश में लगभग आधी से अधिक खेती वर्षा आधारित है। ऐसे में मानसून की थोड़ी सी कमी भी किसानों, खाद्यान्न उत्पादन

और ग्रामीण आय पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञ अल नीनो की संभावनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति भी अपेक्षाकृत धीमी रही है। सामान्य परिस्थितियों में मानसून एक जून के आसपास केरल तट पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसके कुछ दिन देर से पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की शुरुआती देरी हमेशा चिंता का विषय नहीं होती, लेकिन यदि इसके साथ अल नीनो का प्रभाव भी जुड़ जाए तो वर्षा की मात्रा और वितरण दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ पूरी तरह निराशाजनक तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले अन्य मौसमीय कारक इस स्थिति को कुछ हद तक संतुलित कर सकते हैं। विशेष रूप से इंडियन ओशन डायपोल (IOD) और मैडेन-जूलियन ऑस्सिलेशन (MJO) को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। ये दोनों वैश्विक मौसमीय प्रणालियां मानसून को अतिरिक्त ऊर्जा और नमी प्रदान करने में सक्षम होती हैं। जब मैडेन-जूलियन ऑस्सिलेशन भारतीय क्षेत्र से गुजरता है, तब यह बादलों और हवाओं की गतिविधियों को बढ़ाकर वर्षा में वृद्धि कर सकता है। इसी प्रकार अनुकूल इंडियन ओशन डायपोल भी भारतीय मानसून को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार किसी भी संभावित जोखिम को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं है। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अग्रिम तैयारी शुरू करें। मंत्रालय ने जिलास्तर पर विशेष कार्ययोजनाएं तैयार करने और उन्हें तत्काल लागू करने पर जोर दिया है। सरकार का मानना है कि समय रहते की गई तैयारी से संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के साथ हुई बैठकों में कहा है कि किसानों तक मौसम संबंधी जानकारी तेजी से पहुंचाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल संदेश सेवाएं, कॉल सेंटर और कृषि सलाह तंत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि यदि किसी क्षेत्र में कम वर्षा की संभावना हो तो किसानों को पहले से वैकल्पिक फसलों, जल संरक्षण तकनीकों और कृषि प्रबंधन उपायों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित सूखे का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं रहेगा। जलाशयों में जल स्तर, पेयजल उपलब्धता, बिजली उत्पादन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ सकता है। कई राज्यों में पहले से ही भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो जल संकट और गंभीर हो सकता है। इसके अलावा गर्मी की तीव्रता बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी चेतावनी में केवल सूखे की संभावना ही नहीं जताई है, बल्कि मौसम की चरम घटनाओं को लेकर भी आगाह किया है। एजेंसी का कहना है कि अल नीनो के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक वर्षा की कमी बनी रह सकती है। समुद्री और स्थलीय हीटवेव की घटनाओं में भी वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसका अर्थ है कि मौसम का स्वरूप अधिक अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अल नीनो वास्तव में एक प्राकृतिक महासागरीय और वायुमंडलीय घटना है, लेकिन इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाते हैं। जब प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्री हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तब दक्षिण अमेरिकी तट के समीप समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म होने लगता है। यही स्थिति अल नीनो कहलाती है। समुद्र की सतह का यह बढ़ा हुआ तापमान वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है और परिणामस्वरूप दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वर्षा, तापमान और मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इतिहास गवाह है कि अल नीनो के वर्षों में भारत को कई बार कमजोर मानसून का सामना करना पड़ा है। हालांकि हर बार इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता। कई अवसरों पर अन्य मौसमीय कारकों ने इसके प्रभाव को कम भी किया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार महासागरों और वायुमंडलीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय रहते सटीक पूर्वानुमान जारी किए जा सकें।

संपादकीय

नशे पर शिकंजा

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।

वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे की डोज जुटाने के लिये कुछ छात्र व युवा अपराध की राहों में फिसल जाते हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि नियमित रूप से नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी करके तुरंत सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर नशे की खरीद-फरोख्त में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, पासपोर्ट निरस्त करने से भी जहरीले कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों में, जहां सीमा पार से नशे की तस्करी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिये की जा रही है, वहां अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत है। नशा तस्करों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सजा देना, इस अभियान में मददगार साबित होगा।

भारतीय भूमि अतिक्रमण मुद्दे पर घिरे

> “अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी क़ब्ज़ा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है।

गत 27 मार्च को पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक बार भी संघीय संसद को संबोधित नहीं किया था—यहां तक कि अनिवार्य साप्ताहिक प्रश्न-उत्तर सत्रों के दौरान भी नहीं। उनकी चुप्पी तोड़ने और विधायिका के प्रति जवाबदेही दिखाने का दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा था। और फिर रविवार को जब बालेन्द्र शाह संसद में बोले, सभी सन्नाटे में आ चुके थे। उन्होंने अपने आलोचकों को शांत करने के बजाय, मानो डंक मारने वाली मधुमक्खियों का एक झुंड ही छोड़ दिया। जिसे अंग्रेजी में 'पैंडोरा बॉक्स खोलना' कहते हैं।

संसद में दो अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए, शाह ने सबसे पहले कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ प्रयास जारी हैं। लेकिन, फिर उन्होंने यह भी जोड़ा कि न केवल भारत ने नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि भारत के साथ मौजूदा सीमा विवादों की जड़ें 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ हुई सुगौली संधि में हैं, इसलिए उनकी सरकार भारत-नेपाल सीमा चर्चाओं में ब्रिटिश पक्ष को शामिल करने की कोशिश कर रही है। काठमांडू पोस्ट जैसा अखबार भी इस बयान से हैरान था। अगले दिन के सम्पादकीय में अखबार लिखता है— 'सीमा विशेषज्ञों के साथ-साथ उन वरिष्ठ पूर्व सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है, ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसमें भारत ने कभी 'नेपाली अतिक्रमण' का मुद्दा उठाया हो। इसलिए, प्रधानमंत्री का यह बयान भविष्य की सीमा वार्ता में भारत के पक्ष को मज़बूत करता है।'

कोई राष्ट्रीय अख़बार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करे, तो यह उभयपक्षीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। भारत से यदि भूमि विवाद नहीं होता, तो 'बाउंडरी वर्किंग ग्रुप' का गठन क्यों किया गया? संयुक्त तकनीकी समिति ने लगभग 26 वर्षों तक कार्य किया। यह दावा किया गया कि सीमा संबंधी 97 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर लिया गया। शेष तीन प्रतिशत का समाधान करना उनकी क्षमता से परे था। उसमें कालापानी-लिम्पियाधुरा शामिल है—जो 370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा अतिक्रमण है; इसके अलावा 24 किलोमीटर का सुस्ता क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अन्य स्थान भी इसमें हैं। कुल मिलाकर, ऐसे लगभग 71 स्थान हैं जो 606 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल घेरते हैं। इस स्थिति के बने रहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक, सीमांकन के लिए पुराने मानचित्रों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता है।

काश! काठमांडू पोस्ट ने बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की पुस्तक 'द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड द शिफ्टिंग बॉर्डर्स ऑफ नेपाल' में बर्नार्डो माइकल द्वारा की गई टिप्पणी पर ग़ौर किया होता, 'आज भी, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों की उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आधुनिक सीमाओं के निर्धारण की यह परियोजना सदैव एक 'अधूरी परियोजना' ही बनी रहेगी।'

नेपाल के लिए मुश्किल यह है कि लिपुलेख के मुद्दे पर चीन उसके साथ नहीं खड़ा है। लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन भारत का है, उसकी पुष्टि 15 मई, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ व्यापार समझौता है। यह भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था, जिस पर चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग के साथ पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें औपचारिक रूप से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पर सहमति बनी थी। 41-सूत्री संयुक्त बयान के बिंदु 28 में लिपुलेख दर्रे (कियांगला) को औपचारिक रूप से एक द्विपक्षीय सीमा व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में मान्यता दी गई थी।

तब नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि भारत और चीन ने उसकी सहमति के बिना, उसके दावे वाले क्षेत्र से होकर व्यापार करने पर बातचीत की है। बाद के दिनों में नेपाल के तीन प्रधानमंत्रियों केपी शर्मा ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा ने लिपुलेख-लिम्पियाधुरा के बॉल को जमकर खेला। बालेन्द्र शाह से पहले पीएम ओली इस मुद्दे को उठाने 3 सितम्बर, 2025 को पेइचिंग में आहूत थिएनमान चौक विजय दिवस समारोह तक गए लेकिन, चीनी सत्ता प्रतिष्ठान ने उसे अनसुना कर दिया। चीन और भारत तय कर चुके थे कि लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन के बरास्ते जून, 2026 में उभयपक्षीय व्यापार होना है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी क़ब्ज़ा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है। कई सांसद यह चाह रहे हैं कि संसद के रिकार्ड से यह बयान स्पन्ज़ किया जाये। लेकिन, जुबान से निकली बात और कमान से छूटे तीर की वापसी नहीं हो सकती।

नेपाली मीडिया भी हतप्रभ है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट प्रधानमंत्री शाह के बयान को अपरिपक्व मानते हुए लिखता है, 'अगर उन्होंने 'अतिक्रमण' शब्द के बजाय 'सीमा-पार के कब्ज़े' शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो कोई विवाद नहीं होता। दूसरा, नेपाल और भारत के बीच उभयपक्षीय मामले में ब्रिटेन को शामिल करने की इच्छा भी गलत है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह बाउंडरी बातचीत में किसी तीसरे पक्ष को कभी नहीं कबूल करेगा, चाहे वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल के साथ हो।'

जो भी हो, बालेन्द्र शाह का यह बयान भारत-नेपाल संबंधों का कड़वा सच है, जिसे वहां के तथाकथित राष्ट्रवादी नेता और प्रतिक्रियावादी पचा नहीं पा रहे हैं। काठमांडू स्थित सिंह दरबार के गर्भ में वो तमाम दस्तावेज़ ग़र्क़ हैं, जिसमें भूमिहरण संबंधी नक्शा और दस्तावेज़ों की हेराफेरी नेपाली नौकरशाहों ने समय-समय पर की है। नेपाली नेताओं की बौखलाहट की वजहें हैं। नेपाली संसद के निचले सदन में 13 जून, 2020 को लिपुलेख ट्राइजैक्शन की दावेदारी को सही ठहराने के लिए एक फ़र्ज़ी चूचे नक्शा पास किया गया था। उसके सोर्स पर तत्कालीन सांसद सरिता गिरि ने सवाल किया, तो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई।

नेपाल की लीडरशिप जिस 10 सूत्री सुगौली संधि को जपती रहती है, कम

प्रेरणा

प्रकृति के नियमों से दूर होता मानव और बिगड़ती सेहत

मनुष्य का जीवन प्रकृति की गोद में आरंभ हुआ था। हजारों वर्षों तक वह प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीता रहा। उसके भोजन, दिनचर्या, श्रम, विश्राम और सोचने का तरीका प्रकृति के साथ तालमेल में था। यही कारण था कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहता था। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता और सुविधाओं का विकास हुआ, मनुष्य धीरे-धीरे प्रकृति से दूर होता चला गया। आज आधुनिक जीवनशैली ने मनुष्य को अनेक प्रकार की सुविधाएं तो प्रदान कर दी हैं, परंतु इसके साथ ही अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी उसके जीवन का हिस्सा बन गई हैं। प्रकृति के नियमों की उपेक्षा ही आज अधिकांश बीमारियों और तनाव का मुख्य कारण बनती जा रही है।

एक संत अपने शिष्य के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हिरण आनंदपूर्वक कुलांचें भरता हुआ जंगल में दौड़ रहा है। कुछ देर बाद खरगोशों का एक जोड़ा भी मस्ती से उछलता-कूदता दिखाई दिया। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी लिए बड़ी कठिनाई से चलता हुआ वहां से गुजरा। उसका चेहरा पीला था और शरीर कमजोर दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर शिष्य के मन में एक प्रश्न उठा। उसने संत से पूछा कि पशु-पक्षी तो हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देते हैं, जबकि मनुष्य अक्सर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है। ऐसा क्यों होता है?

संत ने बड़े सरल शब्दों में इसका उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि पशु-पक्षी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। वे उतना ही खाते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। भूख लगने पर भोजन करते हैं और भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त श्रम भी करते हैं। उनका जीवन कृत्रिमता से दूर होता है। दूसरी ओर मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को इच्छाओं में और इच्छाओं को लालसाओं में बदल दिया है। अब वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं खाता, बल्कि स्वाद, प्रदर्शन और भोग के लिए खाने लगा है। यही परिवर्तन उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। समय पर भोजन करना, पर्याप्त श्रम करना, विश्राम लेना और संतुलित जीवन जीना इन्हीं नियमों का हिस्सा है। पशु-पक्षी इन नियमों का सहज रूप से पालन करते हैं। वे अपनी भूख से अधिक नहीं खाते और न ही अनावश्यक संग्रह करते हैं। उन्हें कृत्रिम स्वाद, मसालों और दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका शरीर प्राकृतिक भोजन से पोषण प्राप्त करता है और सक्रिय जीवनशैली के कारण वह भोजन आसानी से पच जाता है।

इसके विपरीत मनुष्य ने अपने भोजन को अत्यधिक जटिल बना लिया है। बाजार में उपलब्ध आकर्षक और स्वादिष्ट दिखने वाले खाद्य पदार्थों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तले-भुने भोजन, अत्यधिक मीठे पदार्थ, फास्ट फूड और रासायनिक तत्वों से युक्त खाद्य सामग्री आज सामान्य जीवन का हिस्सा बन गई हैं। स्वाद की तृप्ति के लिए व्यक्ति अपनी वास्तविक शारीरिक आवश्यकताओं की अनदेखी करने लगा है। परिणामस्वरूप मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन संबंधी अनेक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। केवल भोजन ही नहीं, बल्कि जीवनशैली में भी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में पर्याप्त शारीरिक श्रम करता था। खेतों में काम करना, पैदल चलना और प्रकृति के बीच समय बिताना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। आज अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। घंटों तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने समय बिताना तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है। शरीर को जितनी सक्रियता चाहिए, वह नहीं मिल पाती, जिसके कारण अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थिति चिंताजनक है। पशु-पक्षी वर्तमान में जीते हैं। वे न तो अतीत की चिंताओं में उलझते हैं और न ही भविष्य की आशंकाओं से परेशान होते हैं। जबकि मनुष्य का मन लगातार इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा, भय और तनाव से घिरा रहता है। अधिक धन कमाने, अधिक सुविधाएं प्राप्त करने और दूसरों से आगे निकलने की होड़ ने उसके मानसिक संतुलन को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप चिंता, अवसाद, अनिद्रा और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

संत का संदेश केवल भोजन तक सीमित नहीं था। उनका संकेत इंद्रिय संयम की ओर भी था। मनुष्य की जिह्वा, आंख, कान और अन्य इंद्रियां जब नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वे उसे असंतुलित जीवन की ओर ले जाती हैं। संयम का अर्थ सुखों का त्याग नहीं, बल्कि उनका संतुलित उपयोग है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तब उसका जीवन अधिक शांत, स्वस्थ और संतोषपूर्ण बन जाता है।

आज विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है कि प्राकृतिक जीवनशैली स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छ वातावरण और सकारात्मक सोच अच्छे स्वास्थ्य के मूल आधार हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लोगों को प्राकृतिक भोजन अपनाने, शारीरिक गतिविधियां बढ़ाने और तनाव कम करने की सलाह देते हैं। यह वही संदेश है जो संतों और ऋषियों ने सदियों पहले दिया था।

प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि सादगी में ही वास्तविक सुख और स्वास्थ्य छिपा है। यदि हम अपने जीवन को प्रकृति के अधिक निकट ले आएं, भोजन और व्यवहार में संयम अपनाएं तथा अनावश्यक इच्छाओं को सीमित करें, तो अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। स्वस्थ शरीर और शांत मन किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इन्हें बनाए रखने के लिए प्रकृति के नियमों का सम्मान करना आवश्यक है।

इस कथा का सार यही है कि मनुष्य की अधिकांश समस्याओं की जड़ प्रकृति से उसका बढ़ता हुआ विच्छेद है। जितना वह प्राकृतिक जीवन से दूर जाता है, उतना ही रोग, तनाव और असंतोष उसके जीवन में बढ़ते जाते हैं। यदि वह पुनः प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले, तो स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतुलन उसके जीवन में स्वतः लौट सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सादगी, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान को स्थान देना चाहिए। यही दीर्घायु, निरोगता और वास्तविक सुख का सबसे सरल तथा प्रभावी मार्ग है।

गति पकड़ता सेमीकंडक्टर अभियान

वर्तमान दौर में सेमीकंडक्टर की अहमियत किसी से छिपी नहीं रही है। इस संदर्भ में अच्छी बात यह है कि भारत ने भी इसके निर्माण में तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया नीदरलैंड दौरे पर वहां की दिग्गज कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रानिक्स के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए है। एएसएमएल को आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण की रीढ़ मानी जाने वाली उन्नत लिथोग्राफी प्रणालियों के मामले में विश्व के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में से एक माना जाता है। यह अनुबंध इसका प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम में महज एक उपभोक्ता या असेंबलिंग तक ही सीमित न रहकर समूची मूल्य श्रृंखला में स्वयं को स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है। यह करार गुजरात के धोलेरा में 11 अरब डालर के निवेश वाले टाटा के प्रस्तावित चिप निर्माण संयंत्र के लिए बेहद अहम है। धोलेरा को भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में भी देखा जा रहा है।

सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का दृष्टिकोण आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों से प्रेरित है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इलेक्ट्रानिक्स की खपत में तेजी के चलते देश सेमीकंडक्टर के आयात पर बड़ी हद तक निर्भर है। आज के इस दौर में जहां चिप्स आटोमोबाइल एवं दूरसंचार से लेकर रक्षा प्रणालियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे उदीयमान क्षेत्रों की रीढ़ बन चुके हैं, वहां उसकी आधारभूत सामग्री पर बाहरी निर्भरता को घटाना आत्मनिर्भरता के साथ ही आर्थिक सुरक्षा का भी एक अहम अवयव बन गया है। इसका भू-राजनीतिक संदर्भ भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन मुख्य रूप से ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में केंद्रित है। कोविड-19 महामारी से लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी मोर्चे पर तनातनी जैसे पहलुओं ने इस आपूर्ति में गतिरोध पैदा करने का काम किया है। इसने दर्शाया है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं का संकेंद्रण कितना भारी पड़ सकता है। इसका ही परिणाम रहा कि प्रमुख वैश्विक विनिर्माताओं और सरकारों ने उत्पादन में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए चीन से इतर उत्पादन की 'चीन प्लस वन' वाली नीति को अपनाया। इस क्रम में अपने बड़े बाजार, जनसांख्यिकीय गहराई और बढ़ते भूराजनीतिक महत्व के चलते भारत स्वयं को एक आकर्षक वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेमीकंडक्टर निर्माण के निहितार्थ केवल वाणिज्यिक हितों तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण का पहलू अब राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी गहराई से जुड़ा है। विशेष रूप से रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, साइबर बुनियादी ढांचे, दूरसंचार और एआइ संचालित तकनीकों जैसे क्षेत्रों में। इसी कारण सेमीकंडक्टर परिदृश्य महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में भारत का प्रवेश बदलती वैश्विक वास्तविकताओं को स्वीकारने के उसके रवैये को ही रेखांकित करता है। नई दिल्ली ने इसी को ध्यान में रखकर अपना नीतिगत ढांचा भी तैयार किया है। इसके अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपये के आवंटन वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आइएसएम, स्वीकृत चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता जैसी पहल की गई हैं। शायद ही विश्व में कहीं और ऐसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। केंद्रीय बजट में भी आइएसएम 2.0 के दायरे का विस्तार करते हुए सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री, बौद्धिक संपदा विकास, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन और शोध एवं विकास यानी आरएंडडी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्पष्ट है कि भारत की रणनीति अपनी छितरी हुई क्षमताओं को एकीकृत कर उसका लाभ उठाने पर केंद्रित है।

सेमीकंडक्टर अभियान से जुड़ी कई परियोजनाएं अब धरातल पर साकार होने लगी हैं। गुजरात इन गतिविधियों का गढ़ बना हुआ है। धोलेरा में टाटा-पावरचिप फैब्रिकेशन परियोजना तो साणंद में माइक्रोन की एटीएमपी इकाई स्थापित हो रही हैं। असम को टाटा की ओसैट परियोजना हासिल करने में सफलता मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एचसीएल-फाक्सकान संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्वयं को इस परिदृश्य पर मजबूती से उभारने में लगा है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 तो बाकायदा दर्शाती है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी, कर छूट, भूमि दरों में रियायत, बिजली रियायत और कौशल विकास पहलों के माध्यम से केंद्रीय प्रोत्साहनों की पूरक बनकर इस प्रक्रिया को रफ्तार दे रही हैं। केंद्रीय रणनीतिक दूरदर्शिता और राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धा के बीच का यह तालमेल धीरे-धीरे भौगोलिक रूप से एक व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है।

कई स्तरों पर प्रगति के बावजूद इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चिप निर्माण उन उद्योगों में से एक है, जिनके लिए व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पानी की भरोसेमंद एवं सतत आपूर्ति, बिजली की निरंतर उपलब्धता, कुशल कामकाजी आबादी एवं सक्षम आपूर्ति तंत्र का सुनिश्चित होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान विश्व में निर्यातों को लेकर जिस तरह के नियंत्रण एवं भू-राजनीतिक तनाव, खेमेबंदी और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसके प्रभाव से यह क्षेत्र भी अछूता नहीं। इन पहलुओं के सम्मिलित प्रभाव भी इस क्षेत्र के भविष्य की दशा-दिशा को प्रभावित करेंगे।

देखा जाए तो टाटा-एसएमएल अनुबंध, माइक्रोन संयंत्र के संचालन और आइएसएम 2.0 के साथ स्पष्ट है कि भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति संकल्पना के स्तर से वास्तविकता का आकार ग्रहण करने लगी है। इससे एक दीर्घकालिक औद्योगिक क्रांति की बुनियाद रखी जा रही है।

अभियान

देवी की छत्रछाया में बसता विश्वास का पर्वत: गंगोलीहाट की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यह उपाधि केवल उसके मंदिरों या धार्मिक स्थलों के कारण नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक वातावरण के कारण भी है जो यहां की हवा, पर्वतों, नदियों और जनजीवन में घुला हुआ है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे इस राज्य का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक नाम गंगोलीहाट का भी है, जो कुमाऊं क्षेत्र की आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह स्थान न केवल मां हाटकालिका के प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की लोक परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य, सैन्य गौरव और सांस्कृतिक विरासत इसे एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

पिथौरागढ़ जिले में स्थित गंगोलीहाट हिमालयी अंचल का वह क्षेत्र है जहां पहुंचते ही व्यक्ति को प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। दूर-दूर तक फैले पर्वत, घने जंगल, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण मन को एक अलग ही अनुभूति से भर देते हैं। यहां का प्रत्येक दृश्य मानो किसी चित्रकार की उत्कृष्ट कल्पना का परिणाम प्रतीत होता है। यही कारण है कि यहां आने वाला व्यक्ति केवल एक पर्यटक बनकर नहीं रहता, बल्कि इस भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाता है।

समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोलीहाट सदियों से श्रद्धा का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह क्षेत्र कभी कत्यूरी राजाओं के प्रभाव क्षेत्र में था। कत्यूरी शासकों ने कुमाऊं क्षेत्र में अनेक मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया था, जिनमें हाटकालिका मंदिर का विशेष स्थान है। यद्यपि समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन इस मंदिर की धार्मिक महत्ता कभी कम नहीं हुई। आज भी यह स्थान उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा जाता है जैसा सदियों पहले देखा जाता था।

हाटकालिका मंदिर गंगोलीहाट की आत्मा माना जाता है। यह मंदिर मां काली के उस स्वरूप को समर्पित है जिसे शक्ति, साहस, संरक्षण और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहां की शांत वायु, पूजा-अर्चना की ध्वनि और भक्तों की आस्था मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित करती है जो मन को भीतर तक स्पर्श कर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मां कालिका स्वयं अपने भक्तों को संरक्षण और आशीर्वाद प्रदान कर रही हों।

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शंकराचार्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्य किया और अनेक धार्मिक केंद्रों को नई पहचान प्रदान की। गंगोलीहाट का यह मंदिर भी उन्हीं की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस विश्वास ने मंदिर को और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की है।

मां हाटकालिका के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि देवी ने इस क्षेत्र में एक अत्याचारी राक्षस का वध कर लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। तभी से मां को इस क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। स्थानीय लोग किसी भी संकट, बीमारी या कठिनाई के समय मां की शरण में आते हैं और विश्वास करते हैं कि देवी उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। यह आस्था केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि यहां के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। गंगोलीहाट का नाम भारतीय सेना के संदर्भ में भी विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। मां हाटकालिका को कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी माना जाता है। भारतीय सेना की यह रेजिमेंट अपने साहस, अनुशासन और बलिदान के लिए जानी जाती है। सैनिकों का विश्वास है कि मां का आशीर्वाद उन्हें युद्धभूमि में शक्ति और विजय प्रदान करता है। यही कारण है कि अनेक सैनिक महत्वपूर्ण अभियानों से पहले यहां आकर देवी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभाई जाती है।

सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद इस मंदिर का महत्व और अधिक बढ़ गया। युद्ध में भारत की विजय के पश्चात सैनिकों ने अपनी सफलता का श्रेय मां कालिका के आशीर्वाद को भी दिया। बाद में यहां महाकाली की एक विशेष प्रतिमा स्थापित की गई, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। इस घटना ने मंदिर को केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और वीरता के प्रतीक के रूप में भी स्थापित कर दिया। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को थोड़ी दूरी पैदल चलना पड़ता है। यह मार्ग भले ही छोटा हो, लेकिन उसके प्रत्येक कदम में श्रद्धा और उत्साह का अनुभव होता है। जैसे-जैसे श्रद्धालु मंदिर के निकट पहुंचते हैं, उनके भीतर भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होती जाती है। मंदिर परिसर में पहुंचकर वे मां के दर्शन करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच चुनरी चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से लोकप्रिय है। भक्त मां को चुनरी अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप एक चुनरी अपने साथ लेकर जाते हैं। मान्यता है कि यह चुनरी घर में शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कई परिवार इसे अपने घर के पूजा स्थल में रखते हैं और विशेष अवसरों पर इसका उपयोग करते हैं।

गंगोलीहाट केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पारंपरिक बाखलियां आज भी लोगों को पुराने पहाड़ी जीवन की याद दिलाती हैं। पत्थर और लकड़ी से बने घर, पारंपरिक चक्कियां, खेतों की संरचना और ग्रामीण जीवन की सादगी यहां की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखती है। यहां के लोग अपनी परंपराओं को गर्व के साथ संजोए हुए हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद उनकी जीवनशैली में अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है।

प्राकृतिक दृष्टि से भी गंगोलीहाट अत्यंत समृद्ध है। यहां के जंगलों में अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। स्थानीय लोग वर्षों से जड़ी-बूटियों की खेती और उनके उपयोग से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में प्रयुक्त कई महत्वपूर्ण वनस्पतियां इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान भी बनाता है।

गंगोलीहाट आने वाले यात्रियों को यहां के स्थानीय भोजन का स्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। पहाड़ी व्यंजन अपनी सादगी और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय समोसे विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और यहां आने वाले अधिकांश लोग उनका स्वाद चखे बिना नहीं लौटते। इसके अलावा स्थानीय पेय और पारंपरिक भोजन यहां की संस्कृति को समझने का एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं।

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यटन का भी भरपूर अवसर मिलता है। गंगोलीहाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल स्थित हैं। पाताल भुवनेश्वर की रहस्यमयी गुफाएं, चकौड़ी के प्राकृतिक दृश्य और हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाएं पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जो लोग प्रकृति और अध्यात्म दोनों का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं, उनके लिए यह क्षेत्र आदर्श माना जाता है।

नवरात्रि के समय गंगोलीहाट का वातावरण विशेष रूप से आकर्षक हो जाता है। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां की आराधना में भाग लेते हैं। मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और उत्सव के रंग में रंग जाता है। स्थानीय बाजारों में भी विशेष रौनक देखने को मिलती है और श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा वातावरण जीवंत हो उठता है। गंगोलीहाट की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता को समझने का अवसर भी प्रदान करती है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 5 जून को दक्षिण गुजरात को देंगे 1063 करोड़ रुपए से अधिक के जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स की भेंट

प्रधानमंत्री जीआईडीसी अंतर्गत भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड में 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

▶▶ दहेज पीसीपीआईआर में प्रदूषित जल के प्रभावी निस्तारण के लिए 474.61 करोड़ रुपए के एफ्लुएंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा

▶▶ जंबूसर बल्क ड्रग पार्क में 274.96 करोड़ रुपए की लागत से रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन की सुविधाओं से फार्मा क्लस्टर के विकास को मिलेगी नई गति

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 5 जून, 2026 को गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे सूरत से भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के कुल मिलाकर 18,777 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। दक्षिण गुजरात अंचल के विकास को वेग देने वाले इन विकास कार्यों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) अंतर्गत 1063.43 करोड़ रुपए की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शामिल है। इसके तहत भरूच को 894 करोड़ रुपए से अधिक के तथा वलसाड को 169.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भेंट मिलने जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स से दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषित जल निस्तारण तथा ड्रैनेज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री भरूच में 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे

भारत के औद्योगिक विकास में गुजरात हमेशा शीर्ष पर रहा है, जिसमें भरूच जिला केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर आया है। भरूच की औद्योगिक क्षमता को अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री 894 करोड़ रुपए से अधिक के 6 जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। दहेज पीसीपीआईआर औद्योगिक क्लस्टर में सायखा पंपिंग स्टेशन से दहेज के लैंडफॉल पॉइंट तक 90 एमएलएडी क्षमता की ऑफशोर व ऑनशोर एफ्लुएंट निस्तारण पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसमें 5 वर्ष के ऑपरेशन तथा मैंटेनेंस (ओ एंड एम) के साथ सिविल स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कम्पोनेंट्स और पीएलसी स्काडा सिस्टम्स का डिजाइन, इरेक्शन, टेस्टिंग तथा कमीशनिंग शामिल हैं। 474.61 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से दहेज तथा सायखा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के निस्तारण एवं प्रबंधन को और मजबूती मिलेगी।

Sarigam CETP

उल्लेखनीय है कि दहेज पीसीपीआईआर क्षेत्र में मुख्यतः रासायनिक, टेक्सटाइल, फार्मा, डाइज एवं इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए ढाँचागत सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। हाल में इस क्षेत्र में 1,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

इसके अलावा; भरूच जिले के जंबूसर स्थित बल्क ड्रग पार्क में फार्मास्युकिल उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रैनज नेटवर्क तथा सेंट्रल ड्रेन जैसी महत्वपूर्ण अंतरढाँचागत सुविधाएँ विकसित की गई हैं। 274.96 करोड़ रुपए के खर्च से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से बल्क ड्रग पार्क के ढाँचागत विकास को वेग मिलेगा।

प्रधानमंत्री दहेज-2 औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र/परिसंपदा) के लिए 30 एमएलडी ड्रैनेज पंपिंग स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। उल्लेखनीय है कि दहेज-2 औद्योगिक बस्ती में सुवा पंपिंग स्टेशन से अंतिम पंपिंग स्टेशन जेड-93 तक राइजिंग मेन के साथ 30 एमएलडी क्षमता के ड्रैनेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से औद्योगिक ड्रैनेज प्रबंधन अधिक कार्यक्षम बनेगा तथा एकीकृत एफ्लुएंट वहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा; पानोली विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रोड पेवमेंट, क्रॉस ड्रैनेज वर्क, जलापूर्ति नेटवर्क, कम्पाउंड वॉल, पेवर ब्लॉक, वृक्षारोपण और स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न ढाँचागत सुविधाओं का विकास किया गया है। इन विकास कार्यों से इस औद्योगिक क्षेत्र में अधिक अच्छी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

अन्य प्रोजेक्ट्स में अंकलेश्वर में एफ्लुएंट ट्रांसमिशन पाइपलाइन पर इंटरमीडिएट बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट से प्रदूषित जल का कार्यक्षम वहन तो होगा ही, साथ ही पर्यावरणीय मानदंडों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।

इसी प्रकार; दहेज-1 औद्योगिक बस्ती की वर्षा जल वहन क्षमता सुधारने, जल भराव के जोखिम कम करने तथा क्षेत्र के समग्र वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था के ढाँचे को मजबूत करने के लिए नेचुरल ड्रेन-2 का अपग्रेडेशन किया गया है।

वलसाड में 169 करोड़ रुपए से अधिक के जीआईडीसी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण

वलसाड जिले के सरीगाम में प्रधानमंत्री जीआईडीसी के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। इसके तहत सरीगाम स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता 15 एमएलडी से बढ़ाकर 25 एमएलडी की गई है। इससे प्रदूषित जल के शुद्धिकरण की क्षमता में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय मानदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित होगा। इस प्रोजेक्ट में डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कन्स्ट्रक्शन, कमीशनिंग, टेस्टिंग, ट्रायल रन तथा ऑपरेशन मैंटेनेंस और रिपेयरिंग कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा; सरीगाम औद्योगिक बस्ती (क्षेत्र) में संप तथा पंपिंग स्टेशन के साथ एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर आउटफॉल पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट अंतर्गत पंपिंग स्टेशन से लैंडफॉल चैम्बर तथा गहरे समुद्र में निस्तारण के स्थल तक एचडीपीई ऑनशोर व ऑफशोर पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया गया है।

देश में पहली बार : गुजरात में 'सेवा आयुक्तालय' की स्थापना करने का राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

▶▶ गुजरात में उद्योगों के लिए जैसे 'उद्योग आयुक्तालय' कार्यरत है, उसी प्रकार अब सेवा क्षेत्र के लिए अलग 'सेवा आयुक्तालय' कार्यरत होगा : प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶ मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब सर्विस सेक्टर में भी गुजरात बनेगा देश का हब

▶▶ आयुक्तालय में वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपए के 'सर्विस सेक्टर ग्रोथ फंड' की व्यवस्था

▶▶ सेवा क्षेत्र के आईटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स को मिलेगा वेग

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय की घोषणा करते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार गुजरात में सर्विस सेक्टर अर्थात सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए एक अलग 'सेवा आयुक्तालय' की स्थापना करने तथा 'सेवा आयुक्त' का आधिकारिक पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि जैसे उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट उद्योग आयुक्तालय कार्यरत है, उसी प्रकार अब सेवा क्षेत्र के लिए यह नई व्यवस्था शुरू कर गुजरात एक बार फिर देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बनने जा रहा है।

गुजरात पारंपरिक रूप से अपनी मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से अधिक संतुलित और गतिशील अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य सरकार सेवा क्षेत्र में भी विविधीकरण ला रही है। प्रवक्ता मंत्री ने आगे कहा कि 'जीआरआईटी' द्वारा गुजरात में सेवा क्षेत्र के सुदृढ़ और सर्वांगीण विकास के लिए सेवा आयुक्तालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इसके अंतर्गत वर्तमान में सेवा आयुक्तालय की स्थापना और सेवा आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।उन्होंने जोड़ा कि यह आयुक्तालय राज्य और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न सेवा उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करेगा। श्री वाघाणी ने कहा कि परंपरागत उत्पादन आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर गुजरात ने सेवा क्षेत्र आधारित आधुनिक विकास की तरफ ध्यान केन्द्रित किया है। इसके परिणामस्वरूप आईटी, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे तेजी से विकसित हो रहे सेवा क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह आयुक्तालय मुख्य रूप से राज्य के पर्यटन, आईटी और लॉजिस्टिक्स जैसे तेजी से विकसित हो रहे विभिन्न सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने, नई नीतियां बनाने तथा सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का केंद्र बिंदु बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्राप्त वैश्विक सफलता के बाद गुजरात अब सर्विस सेक्टर के लिए भी देश का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत सेवा आयुक्तालय के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 100 करोड़ रुपए के 'सर्विस सेक्टर ग्रोथ फंड' की स्थापना की गई है। इस ग्रोथ फंड का मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमईस और स्टार्टअप्स को ग्रोथ कैपिटल आसानी से और समय पर उपलब्ध कराना है।

अब गुजरात के शहर बनेंगे अधिक स्मार्ट और सुरक्षित

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनट बैठक में 'गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन' को मंजूरी दी : प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶ इस मिशन अंतर्गत राज्य की 17 महानगर पालिकाएं और 151 नगर पालिकाएं वायर फ्री बनेंगी

▶▶ वर्ष 2030 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली की लाइनें पूरी तरह अंडरग्राउंड की जाएंगी

▶▶ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनजीवन अधिक सुरक्षित बनेगा और नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'ग्रीन और स्मार्ट सिटी' के विजन को साकार करते हुए 'गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन' को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।

इस निर्णय के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवक्ता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि 'गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन' अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य के सभी शहरों को चरणबद्ध तरीके से 'वायर फ्री' बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन के प्रारंभिक चरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत राज्य की सभी 17 महानगर पालिकाओं तथा 151 नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों की सुंदरता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि वायर फ्री मिशन के अंतर्गत शहरों में

वर्तमान में मौजूद ओवरहेड विद्युत वितरण नेटवर्क को पूरी तरह अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 14,600 सर्किट किलोमीटर से अधिक हाई टेंशन ओवरहेड नेटवर्क तथा 31,400 सर्किट किलोमीटर से अधिक लो टेंशन ओवरहेड नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 11 केवी ओवरहेड लाइनों को तथा उसके बाद लो टेंशन लाइनों को भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग होने से तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तार टूटने या शॉर्ट सर्किट होने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त; तकनीकी खराबियों में कमी आने से नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा बिना किसी प्रकार की बाधा के निरंतर बिजली उपलब्ध होगी।

प्रवक्ता मंत्री ने जोड़ा कि 'गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन' यह केवल बिजली की लाइनों को बदलने की सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के स्मार्ट, सुंदर और सुरक्षित गुजरात के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है।

12 वर्ष : विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

गुजरात के सभी जिलों में 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' का आयोजन किया जाएगा

▶▶ 08 से 14 जून, 2026 के दौरान जिला मुख्यालयों में सम्मेलनों का आयोजन

▶▶ 'बारह वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' विषय पर वक्तव्य देंगे महानुभाव

▶▶ पद्मश्री पुरस्कार विजेता, विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव रहेंगे मौजूद

गांधीनगर : गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों में 08 से 14 जून के दौरान 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने, राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और अंतिम छोर के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री, सांसद और प्रदेश स्तर से नियुक्त खास वक्ता उपस्थित रहेंगे, जो '12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' विषय पर वक्तव्य देंगे।

प्रत्येक सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित नागरिक तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न एसोसिएशनों, विश्वविद्यालयों, खेल संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखा गया है कि कार्यक्रम में समाज का प्रत्येक वर्ग हिस्सा ले। इस संदर्भ में श्रेष्ठ शिक्षक अवॉर्ड विजेता, श्रेष्ठ किसान तथा खेल क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों सहित साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान देने वाले महानुभाव भी हिस्सा लेंगे।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े जिलों में दो, जबकि अन्य छोटे जिलों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

अहमदाबाद मंडल का चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य एवं जनकल्याण के क्षेत्र में अग्रणी

मई 2026 में व्यापक स्वास्थ्य पहल, आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल और जन-जागरूकता अभियानों का सफल आयोजन

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS), श्रीमती भानुमति शेखर के मार्गदर्शन में मई 2026 के दौरान कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों, आपदा प्रबंधन अभ्यासों और जन-जागरूकता कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया। इन पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए।

1. स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता दिवस:

▶▶ अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस: इस अवसर पर मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती (DRH-SBI) में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लिया और कुल 43 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

▶▶ विश्व अस्थमा दिवस : पूरे मंडल में जागरूकता पोस्टर्स प्रदर्शित किए गए. DRH-SBI में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. जैमिन द्वारा व्याख्यान दिया गया और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया गया। इस अभियान से मंडल के 200 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

▶▶ राष्ट्रीय डेंगू दिवस एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस : इन अवसरों पर सभी रेलवे अस्पतालों, स्वास्थ्य इकाइयों (Health Units) और कॉलोनियों में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां और पोस्टर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

2. महिला स्वास्थ्य और टीकाकरण पर विशेष ध्यानः घातक बीमारियों से बचाव के लिए मंडलीय रेलवे अस्पताल, साबरमती (DRH-SBI) में 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए पूरे महीने (7, 14, 21 और 28 मई 2026 को) 'ह्यूमन पैपिलोमा वायरस' (HPV) टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 40 लाभार्थियों को टीका लगाया गया।

3. मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन सत्रः कर्मचारियों के मानसिक कल्याण और कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डॉ. मनोजकुमार देव, ACMS साबरमती द्वारा विशेष इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए:

▶▶ 26 मई को विश्व सिज़ोफ्रेनिया दिवस पर DRH-SBI में हेल्थ टॉक।

▶▶ 28 मई को इंजीनियरिंग वर्कशॉप, साबरमती में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम।

▶▶ 29 मई को डीजल शेड, वटवा में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र. इन कार्यक्रमों में रेलवे स्टाफ और उनके परिवारों ने भारी संख्या में भाग लिया।

4. प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और सैनिटेशन ड्राइवः

▶▶ मानसून से पहले मलेरिया और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए साबरमती, अहमदाबाद, कांकरिया, गांधीधाम, वीरमगाम, महेसाणा, वटवा और पालनपुर सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों, बैरकों और कार्यालयों में फॉगिंग (Fogging) और लार्वा-नाशक गतिविधियों को अंजाम दिया गया।

▶▶ भीषण गर्मी को देखते हुए सभी कार्यस्थलों और स्टेशनों पर 'हीट स्ट्रोक' (लू) से बचाव संबंधी जागरूकता अभियान चलाए गए।

▶▶ इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और रनिंग रूम (गांधीधाम, भुज, वीरमगाम, डीसा) में आयोजित वैलनेस व हेल्थ चेक-अप कैंपों के माध्यम से कुल 570 कर्मचारियों व लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई।

5. आयुष (AYUSH) ओपीडी सेवाएंः अहमदाबाद मंडल में पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए मई 2026 के दौरान आयुष ओपीडी के तहत कुल 595 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें आयुर्वेद विभाग (अहमदाबाद व गांधीधाम) में 409 मरीज तथा होम्योपैथी विभाग में 186 मरीज शामिल हैं। 6. आपदा प्रबंधन हेतु NDRF के साथ संयुक्त मॉक ड्रिलः अहमदाबाद मंडल की सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए 15 मई 2026 को वटवा स्थित ROH डिपो में एनडीआरएफ (NDRF) के समन्वय से एक पूर्ण पैमाने पर 'मॉक ड्रिल' का आयोजन किया गया. इस अभ्यास में मंडल रेल प्रबंधक (DRM-ADI), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS-ADI), वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी (Sr.DSO-ADI), मेडिकल टीम, एनडीआरएफ के जवानों, एआरएमई-I (ARME-I), एआरटी (ART), फायर सर्विसेज और सिविल एम्बुलेंस सेवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया. इसके अलावा 20 मई को एलसी 51, तलोद-हिम्मतनगर सेक्शन पर भी मॉक ड्रिल संपन्न हुई। पश्चिम रेलवे अपने समस्त रेलकर्मियों की सेहत, सुरक्षा और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए लगातार इस प्रकार के कल्याणकारी और चिकित्सा प्रयासों के प्रति कटिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना संख्या- GEM/2026 /B/7607041 दिनांक 02.06.2026; (1) कार्य का नाम एवं स्थान: कार्य का नाम - कोचिंग डिपो इंदौर, रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) की ट्रेनों में 2 वर्ष की अवधि के लिए ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं (ओबीएचएस) का प्रावधान। **स्थान-** कोचिंग डिपो इंदौर। **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 26,28,48,162.65/- (सभी कर ड्यूटीज एवं जी. एस. टी. सहित); **(3) बयान राशि:** ₹14,64,240/-; **(4) समापन अवधि:** एल. ओ. ए जारी होने की तारीख से 24 माह; **(5) निविदा फार्म जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय:** 12:00:00 बजे दिनांक 25-06-2026 तक जमा करने का समय। **(6) वेबसाईट व नोटिस बोर्ड जहां निविदा संबंधी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है:** निविदायें GeM वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

V/83

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्री आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर नोटिस नंबर S/27/2026 दिनांक 02.06.2026

क्र. नं.	निविदा सं.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
210	WR-TPI-2-2026	भारतीय रेलवे में माल के निरीक्षण के लिए तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों की भागीदारी	टेंडरके अनुसार	29-जून-26

शुद्धिपत्र

नोट 1. शुद्धिपत्र संख्या 1, दिनांक 01.06.2026 द्वारा ,TOD, प्री-बिड प्रश्नों के उत्तर और RFQ शुद्धिपत्र को बढ़ाने के लिए IREPS पर प्रकाशित/अपलोड किया गया ।

नोट 2. शुद्धिपत्र संख्या 2, दिनांक 02.06.2026 द्वारा, TOD को 29.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

विगतवार सूचना EMD, खरीद पर रोक और टेंडर की शर्तों के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 0197

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करो: x.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे

सामग्री प्रबंधन विभाग

विभिन्न सामग्री आपूर्ति

ई-प्रोक्योरमेंट टेंडर नोटिस नंबर S/26/2026 दिनांक 29.05.2026

क्र. नं.	निविदा सं.	आइटम का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	T.O.D.
192	22262432	ईकवेलाइज़र सेट	21 सेट	06-जुलाई-26
193	06263456	हिटाची टाइप ट्रैक्शन मोटर के लिए कार्बन ब्रश	12117 नंग	03-जुलाई-26
194	23262206	अपग्रेडेड हाई टेन्साइल Non-Tr CBC योक	2812 नंग	02-जुलाई-26
195	22262810	AC पेन्टोग्राफ टाइप AM-12 के लिए मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप	1076 नंग	01-जुलाई-26
196	22261549	टेप चेंजर के लिए AOH किट जिसमें 53 आइटम हैं	86 सेट	01-जुलाई-26
197	06262185	चार V डीप ग्रूव एक्सल पुली	459 नंग	30-जुन-26
198	29263006	ट्रांसकेथेटर एओर्टिक वाल्व (बलून एक्सपैंडेबल)	16 नंग	30-जुन-26
199	06261202	कम रखरखाव के लिए स्टेशनरी लेड एसिड	43 सेट	30-जुन-26
200	03262877A	4 mm डाया मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, क्लास M2	23131 कि.ग्रा.	29-जुन-26
201	06261247	नॉन AC कोच के लिए बेटरी बॉक्स	451 नंग	29-जुन-26
202	04261708	गेस फ्रीऑन-22 से IS-5610/1993	15247 कि.ग्रा.	29-जुन-26
203	09255018A	मुख्य ट्रेक्शन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति	1 नंग	29-जुन-26
204	09263007	EMU/MEMU कोच के लिए K टाइप नॉनएस्बेस्टस कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक	95768 नंग	29-जुन-26
205	22263552	बेटरी के साथ 3 फेज़ लोकोमोटिव के लिए स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज़ [Ni-Cd]	13 सेट	29-जुन-26
206	15260606	कोच के लिए बेहतर IRS साइड बफर केसिंग	907 नंग	25-जुन-26
207	23263939	BLC वेगनो के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक	2144 नंग	24-जुन-26
208	27267003	अशोक लेलेन्ड मेक इंजन के लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई के लिए दो साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, साल 2026-2027 और 2027-2028 के लिए।	1 सेट	24-जुन-26
209	06261696	माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रक	228 नंग	24-जुन-26

शुद्धिपत्र

कृपया टेंडर नोटिस नंबर 142 के लिए नंबर S-22-2026, तारीख: 06.05.2026, ड्यू डेट "19.06.2026" पढ़ें।

विगत वार सूचना EMD, खरीद पर रोक और टेंडर की शर्तों के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in पर जाएं। 0188

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें: x.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - राजकोट मण्डल

नए कार्यालय भवन का प्रावधान, कार्यालय और स्टोर का निर्माण और ओआरएच में सुधार

ई-निविदा सूचना सं. 04 वर्ष 2026-27 दिनांक 01/06/2026; ऑफिस का पता: मण्डल रेल प्रबन्धक (इंजी.), पश्चिम रेलवे, कोठी कम्पाउण्ड, राजकोट, गुजरात - 360001; **वेबसाइट:** www.ireps.gov.in

क्र. सं.	ई-निविदा संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशि
1	DRM-RJT-2026-27-E-06	राजकोट (RPF) में रिज़र्व्ड कंपनी के लिए नई ऑफिस भवन का प्रावधान, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, द्वारका, खंभालिया और ओखा में GRP पुलिस थाना में सुधार और राजकोट में 10 बेड वाले GRP बैरक और RPF बैरक के लिए द्वारका और सुरेंद्रनगर में रोड अप्रोच और फर्नीचर का प्रावधान।	₹ 18479426.12	₹ 369600.00
2	DRM-RJT-2026-27-E-07	राजकोट मण्डल : DMC-राजकोट में बर्ड नेटिंग के साथ ऑफिस बिल्डिंग और SSE-P.Way/E/RJT के लिए ऑफिस एवं स्टोर का निर्माण।	₹ 31336009.64	₹ 626700.00
3	DRM-RJT-2026-27-E-08	राजकोट मण्डल: ओखा (1) ORH के लिए सुधार (2) TTE रनिंग रूम का नवीनीकरण (3) कोचिंग डिपो ओखा में व्हील लेथ के अंतर्गत CNC के लिए पाथवे, बोरवेल और दूसरे सहायक कामों का प्रावधान।	₹ 8426232.15	₹ 168500.00

उपरोक्त सभी निविदाओं के लिए: निविदा खोलने की तिथि और समय: 23/06/2026, 15:00 बजे RJT – 040

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly • हमें फोलो करें : x.com/WesternRly

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून को गुजरात दौरे पर : 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

- 7689 करोड़ रुपए के खर्च से निर्मित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (पैकेज 6 और 7) का लोकार्पण
- एनएच-56 के अपग्रेडेशन के अंतर्गत धमासिया-बिटाड़ा और नसारपोर-मलोथा सेक्शन को फोरलेन बनाने के कार्य का शिलान्यास
- हजीरा में 149 करोड़ रुपए के खर्च से बनेगा 6-लेन अंडरपास और फ्लाईओवर, भारी वाहनों की आवाजाही होगी सुगम
- दक्षिण गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, आर्थिक विकास को मिलेगी गति

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 जून, 2026 यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर सूरत-गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे दक्षिण गुजरात क्षेत्र को 12,421 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भेंट देंगे। श्री मोदी वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों का लोकार्पण करेंगे तथा चार अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की इन परियोजनाओं से दक्षिण गुजरात सहित पूरे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा स्थानीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

7689 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (पैकेज 6 और 7) का लोकार्पण

प्रधानमंत्री के करकमलों से वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 36 किलोमीटर लंबे कीम-एना सेक्शन (पैकेज 6) और 27.50 किलोमीटर लंबाई के गणदेवा से एना सेक्शन (पैकेज 7) का लोकार्पण होगा। इन दोनों पैकेजों का निर्माण 7689 करोड़ रुपए के खर्च से किया गया है। इन दोनों पैकेजों में मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, रेल रोड ब्रिज, फ्लाईओवर्स और व्हीकल अंडरपास (वीओपी) का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए दोनों पैकेजों में कुल 70 अंडरपास ओर 2 इंटरचेंज बनाए गए हैं। 8 लेन सड़क की शुरुआत होने से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और त्वरित परिवहन संभव होगा। ड्राइवरों की सुरक्षा और सहूलियत बढ़ाने के लिए इन दोनों पैकेजों पर कुल 7 सुविधा युक्त रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर इन दो पैकेजों के शुरू होने से आने वाले माल ढुलाई और तेज होगी तथा भारतमाला परियोजना के लक्ष्य के अनुसार स्थानीय उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 4732 करोड़ रुपए के खर्च से चार अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिनमें एनएच-56 (पैकेज 4) के धमासिया से बिटाडा/मोवी की फोरलेनिंग, एनएच-56 (पैकेज 6) के नसरपोर से मलोथा की फोरलेनिंग, सूरत हजीरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-53) पर सिक्स लेन वीयूपी यानी व्हीकल अंडरपास (रिलायंस) और वीयूपी कम फ्लाईओवर (कावास) शामिल हैं।

एनएच-56 के अपग्रेडेशन से जनजातीय जिलों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

गुजरात में एनएच-56 के अप्रगेडेशन के अंतर्गत धमासिया-बिटाड़ा और नसारपोर-मलोथा सेक्शन को फोरलेन बनाने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा इस क्षेत्र के जनजातीय जिलों (नर्मदा, तापी, वलसाड, छोटा उदेपुर) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये फोरलेन सड़कें किसानों, उद्योगों और ट्रेड रूट को जोड़कर स्थानीय विकास में योगदान देंगी। 107.67 किलोमीटर की कुल लंबाई की इस फोरलेन सड़क के निर्माण से यात्रा का समय 40 मिनट तक कम हो जाएगा जबकि औसत गति में 75 फीसदी की वृद्धि देखने को मिलेगी। यह फोरलेन सड़क फार्मा, मेडिकल क्लस्टर, फिशिंग सी-फूड क्लस्टर, इस क्षेत्र के जनजातीय जिलों तथा लॉजिस्टिक्स नोड्स (एक एयरपोर्ट, 02 रेलवे स्टेशन और 02 बंदरगाह) को जोड़ेगी।

हजीरा में बनेगा सिक्स लेन का फ्लाईओवर और व्हीकल अंडरपास

राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के हजीरा बंदरगाह-सूरत विभाग पर लगभग 149 करोड़ रुपए की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। नए 6-लेन फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण से हजीरा पोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भारी मालवाहक वाहनों की अवरोध मुक्त एवं त्वरित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इससे समुद्री व्यापार और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सूरत के स्थानीय लोगों को सुरक्षित और यातायात जाम से मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण से हजीरा बंदरगाह के निकट स्थित भारी औद्योगिक क्षेत्र में भीड़ कम होगी और सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा।

मानसून से पहले गुजरात अलर्ट: 'जीरो कैजुअल्टी' के लक्ष्य के साथ प्रशासन सज्ज : मुख्य सचिव श्री एम. के. दास

- मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की अध्यक्षता में गांधीनगर में प्री-मानसून उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई
- संबंधित विभागों और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मानसून पूर्व तैयारियों तथा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर प्रस्तुतियां दीं
- राज्य में बचाव कामकाज के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैयार

गांधीनगर : मुख्य सचिव श्री एम. के. दास की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में आगामी मानसून की संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों तथा विभागों की प्री-मानसून उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, मुख्य वन संरक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि गुजरात का प्रशासन मानसून से पहले 'जीरो कैजुअल्टी' के लक्ष्य के साथ पूरी तरह सज्ज है। उन्होंने राज्य में मानसून के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने भारी बारिश या बाढ़ की स्थिति में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक वस्तुओं, दवाओं और अन्य जरूरी आपूर्ति का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मानसून के आगमन से पहले राज्य, जिला तथा तहसील स्तर के कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशानुसार मानसून के दौरान राज्य में किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शेष सड़कों तथा सीवर-लाइन के कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारी वाहनों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों और पुलों की आवश्यक मरम्मत का कार्य अभी से पूरा करने के लिए सड़क एवं भवन विभाग को निर्देश दिए।

उन्होंने आगे कहा कि पहली बारिश और तूफान के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर अभी से पेड़ों की छंटाई करें, ताकि ट्रैफिक जाम और जनहानि से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने सरदार सरोवर और उकाई सहित बड़े बांधों में जलस्तर और पानी की आय पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री जयंती रवि ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा के समय बचाव कार्य के लिए राज्य में एनडीआरएफ की 14 तथा एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की जाएंगी। ये सभी टीमें पर्याप्त संख्या में बोट, लाइफ जैकेट तथा अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे आधुनिक संसाधनों से सज्ज होंगी। उन्होंने जोड़ा कि स्टेट मॉनसून डिजास्टर प्लान के अनुसार हर विभाग के सम्बद्ध अधिकारियों को जिलों के साथ समन्वय में रहकर कार्य करना होगा।

इस बैठक में स्टेट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के समन्वय के साथ राज्य के मौसम, केंद्रीय सुरक्षा बल, शहरी विकास, स्वास्थ्य, सड़क एवं भवन, जलापूर्ति जैसे विभागों द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया।

इस बैठक में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सैन्य बलों के अधिकारी, बीएसएफ, कोस्टगार्ड, सीआरपीएफ, सीडब्लूसी, आरएएफ, रेलवे, बीएसएनएल, दूरदर्शन, इसरो तथा ऑल इंडिया रेडियो आदि के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

सूरत के नासिरनगर विध्वंस मामले में कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

चार दिन पहले, बिना किसी पूर्व सूचना या मौखिक या लिखित नोटिस के, सूरत नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जेसीबी मशीन से लैस पुलिस काफिले के साथ, अचानक नासिर नगर की झुग्गी बस्ती में पहुंचे और तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया। इससे एक हजार से अधिक घरों के निवासियों में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई। नासिर नगर में हुई इस अचानक तोड़फोड़ के पीछे उठे जटिल प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। चार दिनों से पीड़ितों को कोई जवाब नहीं मिला है, न ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आए नेताओं को।

सवाल यह उठता है कि अगर एसएमसी ने यह तोड़फोड़ नहीं करवाई, तो किसके इशारे पर करवाई गई? क्या सत्ताधारी पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ मिलीभगत करने वाले किसी बिल्डर के कारण एसएमसी और पुलिस के दबाव में यह तोड़फोड़ करवाई गई?

इस विध्वंस के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग किसने की? एसएमसी के बाद, और किसने? कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा, एसएमसी के अधिकारी भी कह रहे हैं कि यह काम एसएमसी ने नहीं किया। तो मानसून के बीच इन घरों को गिराने के पीछे किसका हाथ है?

उपभोक्ता संरक्षण और अनुसंधान केंद्र ऐसे कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के साथ-साथ सदर विध्वंस के पीछे के सभी किरदारों को बेनकाब करने और बेघर लोगों को आगामी मानसून के मौसम के दौरान आवास प्रदान करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करेगा और सदर विध्वंस के पीड़ितों को न्याय दिलाएगा।

अवैध घुसपैठ पर अहमदाबाद में बड़ा शिकंजा, 166 बांग्लादेशी पकड़े गए, 300 से अधिक संदिग्ध हिरासत में

अहमदाबाद। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और शहर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए विशेष अभियान में 300 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में इनमें से 166 लोगों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई है, जबकि शेष लोगों के पहचान पत्रों, निवास संबंधी दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की जा रही है। इस कार्रवाई ने शहर में लंबे समय से सक्रिय अवैध घुसपैठ नेटवर्क और उससे जुड़े दलालों के पूरे तंत्र को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार 2 जून की रात शुरू किया गया यह अभियान अहमदाबाद के चंडोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में चलाया गया। इन क्षेत्रों को लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और संदिग्ध गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल, क्राइम ब्रांच की विशेष टीमें और खुफिया इकाइयों ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों, निर्माण स्थलों, मजदूर आवासों, छोटे होटलों और व्यावसायिक परिसरों की गहन तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान जिन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए या जो अपनी पहचान साबित नहीं कर सके, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कैंपस लाया गया।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में चंडोला क्षेत्र में लगातार चल रही पुलिस कार्रवाइयों के कारण अवैध रूप से रह रहे लोग अब एक ही स्थान पर नहीं ठहरते। पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटे-छोटे

समूहों में रहने लगे हैं। यही कारण है कि इस बार अभियान को केवल एक इलाके तक सीमित रखने के बजाय पूरे शहर में व्यापक स्तर पर चलाया गया। पुलिस का मानना है कि अवैध घुसपैठियों ने स्थानीय पहचान बनाकर और किराए के मकानों में रहकर अपनी मौजूदगी को छिपाने की कोशिश की है।

जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि इनमें से कई लोग वर्षों से शहर में रह रहे थे और स्थानीय स्तर पर कामकाज कर रहे थे। कुछ लोग निर्माण कार्य, छोटे उद्योगों, घरेलू श्रम और अन्य असंगठित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर चुके थे। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि कई लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान बदल ली थी, जिससे उनकी वास्तविक नागरिकता का पता लगाना कठिन हो गया था। अब पुलिस विभिन्न सरकारी अभिलेखों और पहचान प्रणालियों के माध्यम से इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है।

पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों ने जांच एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। हिरासत में लिए गए कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने स्वीकार किया है कि वे अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में काम करके जो धन कमाते थे, उसे नियमित रूप से बांग्लादेश में अपने परिवारों तक पहुंचाते थे। इसके लिए एक संगठित नेटवर्क सक्रिय था, जिसमें स्थानीय और अंतरराज्यीय स्तर के दलाल शामिल थे। पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि सबसे पहले नकद राशि कोलकाता भेजी जाती थी और वहां से विभिन्न माध्यमों के जरिए उसे बांग्लादेश पहुंचाया जाता था।

जांच में यह भी पता चला है कि पारंपरिक हवाला जैसे तरीकों के अलावा कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन डिजिटल माध्यमों के जरिए सीमापार धन हस्तांतरण की आशंका को देखते हुए साइबर क्राइम की टीमों को भी जांच में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल फोन, डिजिटल लेन-देन के रिकॉर्ड और संपर्क सूत्रों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन गतिविधियों के पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन दलालों और एजेंटों तक पहुंचना है, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने, रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और धन भेजने की व्यवस्था करने में भूमिका निभाते हैं।

पुलिस का मानना है कि जब तक इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक केवल अवैध प्रवासियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं होगा। इसी कारण अब जांच का दायरा केवल हिरासत में लिए गए लोगों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने किसी भी स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। शहर के विभिन्न इलाकों में सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और संदिग्ध दस्तावेजों वाले लोगों की जांच की जाएगी। पुलिस ने मकान मालिकों, उद्योग संचालकों और व्यवसायियों से भी अपील की है कि वे अपने यहां काम करने वाले या रहने वाले लोगों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाकर ही अवैध घुसपैठ की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

गुजरात में हाल के वर्षों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए हैं, लेकिन अहमदाबाद में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लिया जाना इस कार्रवाई को विशेष बनाता है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इन लोगों का किसी अन्य आपराधिक गतिविधि या संगठित नेटवर्क से कोई संबंध था। फिलहाल सभी की निगाहें जांच के अगले चरण पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले से जुड़े कई और महत्वपूर्ण खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के अवैध रूप से देश में रहने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं फर्जी दस्तावेज तैयार करने, पहचान छिपाने और अवैध वित्तीय लेन-देन में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

रेलवे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सुरक्षित व्यवहार अपनाने का संदेश

आरपीएफ असारवा द्वारा आईटीआई कुबेरनगर में आयोजित किया गया विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम

रेलवे में पत्थरबाजी, अनधिकृत रेल अतिक्रमण, चैन पुलिंग, रन-ओवर जैसी दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट असारवा द्वारा आईटीआई कुबेरनगर में एक विशेष रेलवे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री अंशुमान राम त्रिपाठी, आईआरपीएफएस, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ, अहमदाबाद मंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को रेलवे में होने वाली पत्थरबाजी, रेलवे पटरियों पर अनधिकृत रूप से चलने अथवा उन्हें पार करने से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों तथा इनके कानूनी परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी एवं रेलवे क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश न केवल रेलवे संपत्ति

को क्षति पहुंचाते हैं, बल्कि यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों के जीवन को भी गंभीर जोखिम में डालते हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से रेलवे पटरियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, चलती ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने तथा सदैव सुरक्षित व्यवहार अपनाने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे इस कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी को अपने परिवारजनों, मित्रों एवं पड़ोसियों तक पहुंचाकर रेलवे सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर अवसरों के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया तथा उन्हें नशे एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की प्रेरणा दी।

यह कार्यक्रम प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल थाना असारवा श्री मनु छौक्कर एवं उनकी टीम के विशेष प्रयासों से आयोजित किया गया। आरपीएफ असारवा द्वारा निरंतर चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियानों जैसे "संवाद" एवं सामुदायिक सहभागिता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। गत वर्ष जहां पत्थरबाजी की 9 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं वर्ष 2026 में मई माह तक केवल 2 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। यह उल्लेखनीय उपलब्धि आरपीएफ के सतत प्रयासों का प्रतिफल है। इसके बावजूद आरपीएफ आसारवा ऐसी घटनाओं को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्यरत है। कार्यक्रम में श्री नीरव विष्णुभाई देसाई, प्राचार्य, आईटीआई कुबेरनगर सहित संस्थान के अन्य शिक्षकों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। लगभग 200 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। रेलवे सुरक्षा का सशक्त संदेश देते हुए कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

NEET, CUET और NTA के फिर से विवादों में घिरने के बाद, छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में हाल ही में हुए NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कांड का खुलासा CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर हुए विवाद के तुरंत बाद हुआ। इन दोनों विवादों के सुलझने से पहले ही, स्नातक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली CUET परीक्षा में देरी और अफरा-तफरी मच गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें घंटों तक कपाशेरा पुलिस स्टेशन में बिना किसी सूचना के रखा गया।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के सामने आने के बाद सोमवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के बाहर कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान, छात्र समूहों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के विघटन और परीक्षा संबंधी सभी अनियमितताओं की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में

जांच की मांग की। लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने वाली इन अनियमितताओं के सामने आने के बावजूद, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एनटीए अधिकारियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है।

इससे साफ पता चलता है कि एनटीए (नेशनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन) इन परीक्षाओं में बैठने वाले लाखों छात्रों के प्रति उदासीन है। और यह पहली बार नहीं है जब एनटीए पर सवाल उठाए गए हैं। पहले भी इसके कामकाज पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती रही है। आखिर, NEET 2024 का घोटाला कौन भूल सकता है? फिर भी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय एनटीए की जवाबदेही तय करने में नाकाम रहे हैं।

लोकतांत्रिक इतिहास में नया अध्याय: 10 जून को पीएम मोदी रचेंगे सबसे लंबे निर्वाचित प्रधानमंत्रित्व का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 10 जून का दिन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करेंगे, जो अब तक देश के किसी भी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को हासिल नहीं हुआ है। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे मोदी 10 जून को प्रधानमंत्री पद पर 4,399 दिन पूरे कर लेंगे और इसके साथ ही वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि अब तक यह रिकॉर्ड देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था। नेहरू ने स्वतंत्र भारत की नींव रखने और संसदीय लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा लगातार कई वर्षों तक देश का नेतृत्व किया था। अब लगभग छह दशक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर देश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2019 में भाजपा ने और भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की। वर्ष 2024 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को फिर से बहुमत मिलने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार उन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनावों में जनता का समर्थन हासिल कर सत्ता में अपनी निरंतरता बनाए रखी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहना केवल राजनीतिक रणनीति का परिणाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे व्यापक जनाधार, संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्व कौशल और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता भी होती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का यह रिकॉर्ड केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व की निरंतरता का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। मोदी पहले ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार प्रधानमंत्रित्व के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे और लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया था।